

## GAIL



GAIL (India) Limited celebrated the 75th Republic Day. On this momentous occasion, Sandeep Kumar Gupta, CMD, GAIL unfurled the National Flag in the

presence of top level management and employees. Addressing the gathering on #RepublicDay, Sandeep Kumar Gupta said, "GAIL is in sync with the vision of Government of India towards Natural Gas-based economy by developing infrastructure and business around Natural Gas. GAIL is committed towards the vision of Net Zero by taking sustainable development steps in this direction".

# Govt halves Budget support to oil cos

PTI / New Delhi

The government has halved the amount of equity infusion in state-owned fuel retailers to Rs 15,000 crore for supporting their investments in energy transition projects, the finance ministry has said.

Finance Minister Nirmala Sitharaman had on February 1 last year while presenting the annual Budget for 2023-24 fiscal (April 2023 to March 2024) announced equity infusion of Rs 30,000 crore in Indian Oil Corporation (IOC), BPCL and HPCL to support the three state-owned firms' energy transition plans.

Alongside, she had also proposed Rs 5,000 crore for buying crude oil to fill strategic underground storages at Mangalore in Karnataka and Visakhapatnam in Andhra Pradesh that In-



**The FM in the previous budget had announced equity infusion of ₹30,000 crore in IOC, BPCL and HPCL to support the 3 firms' energy transition plans**

dia has built to guard against any supply disruptions. That plan has also been deferred in view of emerging trends in oil markets, the finance ministry said.

While other state-owned oil

companies such as ONGC and GAIL (India) Ltd too have lined up billions of dollars of investment to achieve net zero carbon emissions. The finance ministry in a post on X detailing the outcome of the budget announcements, informed about the halving of equity support and deferring of filling strategic reserves.

"The Budget (for 2023-34) provides Rs 35,000 crore for priority capital investments towards energy transition and net zero objectives, and energy security by the Ministry of Petroleum and Natural Gas," it said.

Of this, Rs 30,000 crore was towards capital support to oil marketing companies IOC, BPCL and HPCL for green energy and net zero initiatives, and the remaining for purchase of crude oil for caverns at Mangalore and Visakhapatnam, it said.



# Govt halves Budget support to oil firms

PTI ■ NEW DELHI

The government has halved the amount of equity infusion in state-owned fuel retailers to Rs 15,000 crore for supporting their investments in energy transition projects, the finance ministry has said.

Finance Minister Nirmala Sitharaman had on February 1 last year while presenting the annual Budget for 2023-24 fiscal (April 2023 to March 2024) announced equity infusion of Rs 30,000 crore in Indian Oil Corporation (IOC), Bharat Petroleum Corporation Ltd (BPCL) and Hindustan Petroleum Corporation Ltd (HPCL) to support the three state-owned firms' energy transition plans.

Alongside, she had also proposed Rs 5,000 crore for buying crude oil to fill strategic

underground storages at Mangalore in Karnataka and Visakhapatnam in Andhra Pradesh that India has built to guard against any supply disruptions. That plan has also been deferred in view of emerging trends in oil markets, the finance ministry said.

While other state-owned oil companies such as Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) and GAIL (India) Ltd too have lined up billions of dollars of investment to achieve net zero carbon emissions, the equity support was limited to the three fuel retailers, who had suffered huge losses in 2022 when they held retail petrol, diesel and cooking gas (LPG) prices despite a spike in raw material (crude oil) prices following Russia's invasion of Ukraine.

The finance ministry in a post



on X detailing the outcome of the budget announcements, informed about the halving of equity support and deferring of filling strategic reserves.

"The Budget (for 2023-34) provides Rs 35,000 crore for priority capital investments towards energy transition and net zero objectives, and energy security by the Ministry of

Petroleum and Natural Gas," it said.

Of this, Rs 30,000 crore was towards capital support to oil marketing companies IOC, BPCL and HPCL for green energy and net zero initiatives, and the remaining for purchase of crude oil for caverns at Mangalore and Visakhapatnam, it said.

"During the Expenditure Finance Committee meeting held on November 30, 2023, it was decided a maximum of Rs 15,000 crore could be provided for equity infusion into OMCs in FY 2023-24," the finance ministry said without detailing the reasons for the decision.

Industry sources said the decision may be linked to a boost in profitability of the three firms in the current fiscal which has partly covered for the losses in the previous 2022-23 (April 2022 to March 2023) fiscal. The three are making good profit this year as the freeze in retail selling prices extends into the 21st month despite crude oil prices having softened.

"Based on the recommendations of EFC, approval of the CCEA (Cabinet Committee

on Economic Affairs) is being sought. The draft note for approval of CCEA is under process in MoPNG (Ministry of Petroleum and Natural Gas)," the ministry said.

The board of IOC and BPCL had last year approved rights issues to raise up to Rs 22,000 crore and Rs 18,000 crore, respectively. The government was to participate in the rights issue.

Sources said the two firms plan to halve the rights issue and complete them by March 31.

In case of HPCL, the government will not make any direct equity infusion as it had sold its majority stake in the company to ONGC in 2018. The infusion is likely to be through ONGC which will make the preferential issue of shares to the government.

# सरकार ने तेल कंपनियों का बजट समर्थन आधा किया

## रणनीतिक तेल भंडार भरना टाला

नई दिल्ली, 26 जनवरी (भाषा)।

सरकार ने ऊर्जा बदलाव यानी हरित ऊर्जा से जुड़ी परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के खुदरा ईंधन विक्रेताओं में किए जाने वाले इक्विटी निवेश की राशि को आधा कर 15,000 करोड़ रूपए कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी दी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले साल एक फरवरी को वित्त वर्ष 2023-24 का आम बजट पेश करते हुए इंडियन आयल कारपोरेशन (आईओसी), भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) में 30,000 करोड़ रूपए के इक्विटी निवेश की घोषणा की थी।

यह निवेश इन तीनों कंपनियों द्वारा ऊर्जा बदलाव योजनाओं में किए जाने वाले निवेश का समर्थन करने के लिए किया जाना था। इसके साथ ही, वित्त मंत्री ने कर्नाटक के मैंगलोर और आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में रणनीतिक भूमिगत भंडारण को भरने के लिए कच्चा तेल खरीदने को लेकर 5,000 करोड़ रूपए का भी प्रस्ताव किया था। इसका इस्तेमाल किसी भी आपूर्ति व्यवधान से बचाने के लिए होना था।

वित्त मंत्रालय ने कहा कि तेल बाजारों में उभरते रुझानों को देखते हुए उस योजना को भी स्थगित कर दिया गया है। अन्य सरकारी तेल कंपनियों जैसे ओएनजीसी और गेल (इंडिया) लिमिटेड ने भी शुद्ध रूप से शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने के लिए अरबों डालर का निवेश किया है। हालांकि, इक्विटी समर्थन तीन ईंधन खुदरा विक्रेताओं तक सीमित था। इन कंपनियों को 2022 में लागत से कम मूल्य पर पेट्रोलियम उत्पाद बेचने के चलते भारी नुकसान हुआ था।

वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन

वित्त मंत्रालय ने कहा कि तेल बाजारों में उभरते रुझानों को देखते हुए उस योजना को भी स्थगित कर दिया गया है। अन्य सरकारी तेल कंपनियों जैसे ओएनजीसी और गेल (इंडिया) लिमिटेड ने भी शुद्ध रूप से शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने के लिए अरबों डालर का निवेश किया है।

हालांकि, इक्विटी समर्थन तीन ईंधन खुदरा विक्रेताओं तक सीमित था। इन कंपनियों को 2022 में लागत से कम मूल्य पर पेट्रोलियम उत्पाद बेचने के चलते भारी नुकसान हुआ था।

का विवरण देते हुए इक्विटी समर्थन को आधा करने और रणनीतिक भंडार भरने को टालने के बारे में जानकारी दी। इसमें कहा गया है, 'पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में ऊर्जा बदलाव और शुद्ध रूप से शून्य कार्बन उत्सर्जन उद्देश्यों तथा ऊर्जा सुरक्षा के लिए प्राथमिकता वाले पूंजी निवेश के लिए 35,000 करोड़ रूपए प्रदान किया है।' इसमें से 30,000 करोड़ रूपए तेल विपणन कंपनियों आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल को हरित ऊर्जा और शुद्ध रूप से शून्य कार्बन उत्सर्जन पहल के लिए पूंजी समर्थन के लिए थे।

शेष मैंगलोर और विशाखापत्तनम में रणनीतिक भूमिगत भंडारण क्षेत्रों के लिए कच्चे तेल को खरीद को लेकर थे। वय वित्त समिति की 30 नवंबर, 2023 को आयोजित बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि वित्त वर्ष 2023-24 में तेल विपणन कंपनियों में इक्विटी निवेश के लिए अधिकतम 15,000 करोड़ रूपए प्रदान किए जा सकते हैं। हालांकि वित्त मंत्रालय ने निर्णय के कारणों का विवरण नहीं दिया। उद्योग सूत्रों ने कहा कि यह निर्णय चालू वित्त वर्ष में तीन कंपनियों के लाभ में वृद्धि से जुड़ा हो सकता है।





# सरकार ने तेल कंपनियों को बजट समर्थन किया आधा

नई दिल्ली (भाषा)। सरकार ने ऊर्जा बदलाव यानी हरित ऊर्जा से जुड़ी परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के खुदरा ईंधन विक्रेताओं में किए जाने वाले इक्विटी निवेश की राशि को आधा कर 15,000 करोड़ रुपए कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी दी।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले साल एक फरवरी को वित्त वर्ष 2023-24 का आम बजट पेश करते हुए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (आईओसी), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) में 30,000 करोड़ रुपये के इक्विटी निवेश की घोषणा की थी। यह निवेश इन तीनों कंपनियों द्वारा ऊर्जा बदलाव योजनाओं में किए जाने वाले निवेश का समर्थन करने के लिए किया जाना था।

इसके साथ ही वित्त मंत्री ने कर्नाटक के मंगलोर और आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में रणनीतिक भूमिगत भंडारण को भरने के लिए कच्चा तेल खरीदने को लेकर 5,000 करोड़ रुपये का भी प्रस्ताव किया था। इसका इस्तेमाल किसी भी आपूर्ति व्यवधान से बचाने के लिए होना था।

वित्त मंत्रालय ने कहा कि तेल बाजारों में उभरते रुझानों को देखते हुए उस योजना को भी स्थगित कर दिया गया है। अन्य सरकारी तेल कंपनियों जैसे ओएनजीसी और गेल (इंडिया) लिमिटेड ने भी शुद्ध रूप से शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने के लिए अरबों डॉलर का

निवेश किया है। हालांकि, इक्विटी समर्थन तीन ईंधन खुदरा विक्रेताओं तक सीमित था। इन कंपनियों को 2022 में लागत से कम मूल्य पर पेट्रोलियम उत्पाद बेचने के चलते भारी नुकसान हुआ था।

वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन का विवरण देते हुए इक्विटी समर्थन को आधा करने और रणनीतिक भंडार भरने को टालने के बारे में जानकारी दी। इसमें कहा गया है, 'पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2023-34 के

बजट में ऊर्जा बदलाव और शुद्ध रूप से शून्य कार्बन उत्सर्जन उद्देश्यों तथा ऊर्जा सुरक्षा के लिए प्राथमिकता वाले पूंजी निवेश के लिए 35,000 करोड़ रुपये प्रदान किया है।'

इसमें से 30,000 करोड़ रुपये तेल विपणन कंपनियों आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल को हरित ऊर्जा और शुद्ध रूप से शून्य कार्बन उत्सर्जन पहल के लिए पूंजी समर्थन के लिए थे। शेष मंगलोर और विशाखापत्तनम में रणनीतिक भूमिगत भंडारण क्षेत्रों के लिए कच्चे तेल की खरीद को लेकर थे। व्यय वित्त समिति की 30 नवम्बर, 2023 को आयोजित बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि वित्त वर्ष 2023-24 में तेल विपणन कंपनियों में इक्विटी निवेश के लिए अधिकतम 15,000 करोड़ रुपये प्रदान किए जा सकते हैं। हालांकि वित्त मंत्रालय ने निर्णय के कारणों का विवरण नहीं दिया।

■ रणनीतिक तेल भंडार भरना भी टाला

ENERGY TRANSITION

# Govt halves equity infusion in OMCs to ₹15K cr

ENS ECONOMIC BUREAU @ New Delhi

FINANCE ministry has halved the amount of equity infusion in state-owned fuel retailers to ₹15,000 crore to support their investments in energy transition projects, and also has deferred the plans to purchase crude oil worth ₹5,000 crore to fill strategic underground storages.

The ministry made this decision after considering the emerging trends in oil markets. "The plan for the purchase of crude oil worth ₹5,000 crore for caverns at Mengaluru & Visakhapatnam has been recommended for deferral by the Department of Expenditure, Ministry of Finance. This recommendation takes into account the emerging trends in oil markets," stated the finance ministry.

India, as the world's third-largest oil importer and consumer, relies on imports for over 80% of its oil requirements. In order to safe-



**₹30,000 crore capital support to OMCs (IOCL, BPCL, HPCL) for green energy and net zero Initiatives: During Expenditure Finance Committee meeting held on November 30, 2023, it was decided maximum of ₹15,000 crore could be provided for equity infusion into OMCs in FY 2023-24** — The Ministry of Finance



guard against supply disruptions, the country has established strategic storage facilities at three locations in southern India. These facilities have the capacity to store over 5 million tons of oil, providing a crucial buffer to ensure a stable and secure

oil supply.

In 2023, during the presentation of the national budget, finance minister Nirmala Sitharaman allocated ₹30,000 crore for Indian Oil Corporation (IOC), Bharat Petroleum Corporation Ltd (BPCL), and Hindustan Petroleum Corporation Ltd (HPCL) to support the energy transition plans.

She also proposed ₹5,000 crore for purchasing crude oil to fill strategic underground storages in Mangalore, Karnataka, and Visakhapatnam, Andhra Pradesh.

These storages were established by the government as a precautionary measure against potential supply disruptions.

While other state-owned oil companies such as Oil and Natural Gas Corporation (ONGC) and GAIL (India) Ltd have also outlined substantial investments to achieve net-zero carbon emissions, the equity support was specifically directed to the three fuel retailers.

"₹30,000 crore capital support to OMCs (IOCL, BPCL, HPCL) for green energy and net zero initiatives: During Expenditure Finance Committee meeting held on November 30, 2023, it was decided maximum of ₹15,000 crore could be provided for equity infusion into OMCs in FY 2023-24," said the ministry.